भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2300
जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

पूर्वोत्तर राज्यों में भारी उद्योग को बढ़ावा देने की योजना

2300. श्री के. भावानंद सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार का सृजन करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मणिपुर में भारी उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देने की कोई योजना/स्कीम बनाई है क्योंकि मणिपुर में ऐसा कोई उद्योग नहीं है;

(ख) क्या केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां/पीएसयू ही पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मणिपुर में निवेश करना चाहते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): जी, हाँ। सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों के लिए एक योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 चलाती है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

यह योजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है।

(ख): भारी उद्योग विभाग की भूमिका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को प्रशासित करना है। भारी उद्योग विभाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवेश योजनाओं संबंधित कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखता है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

******